www.sanjanabharati.com
दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर से प्रकाशित। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व उत्तराखंड में प्रसारित
facebook.com/Sanjanabharati

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

संजना भारती

RNI No. : DELHIN/2016/70240

आपका भरोसा, हमारी ताकत

2 वोट बैंक के लालच ने बर्बाद किया हिमाचल...
3 अद्भूत गर्व, एकता और देशभक्ति की भावना को जगाता...
4 शिक्षा के साथ-साथ संस्कारों का विद्यार्थी जीवन...

वर्ष: 9 | अंक: 285 | दिल्ली, शुक्रवार, 8 अगस्त 2025 | पृष्ठ संख्या: 4 | मूल्य: 1 रुपया

संक्षिप्त समाचार

ममता बनर्जी की सरकार में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है: नड्डा

पश्चिम बंगाल (एजेन्सी)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे पी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर राज्य पुलिस की मौजूदगी में हुए हमले के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बृहस्पतिवार को आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि यह घटना राज्य में उनकी सरकार में कानून-व्यवस्था के पूरी तरह से ध्वस्त होने को दर्शाती है। नड्डा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, अराजकता और राजनीतिक हिंसा की इस संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ममता बनर्जी को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

गंगा यमुना और शारदा समेत कई प्रमुख नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर

उत्तर प्रदेश (एजेन्सी)। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित जल भरण क्षेत्र में व्यापक वर्षा होने से गंगा, यमुना और शारदा समेत राज्य की अनेक प्रमुख नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। उफनती नदियों की बाढ़ से राज्य के अनेक जिलों के सैकड़ों गांवों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। बलिया में बाढ़ के पानी में डूबने से एक लड़के की मौत हो गयी। मौसम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, प्रदेश में मानसून सक्रिय है और अगले एक सप्ताह के दौरान पूरे राज्य में बारिश का सिलसिला कमोबेश जारी रह सकता है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को गंगा नदी कछला ब्रिज (बदायूं), गाजीपुर, छतनाग और फाफामऊ (प्रयागराज), बलिया, मिजार्पुर और वाराणसी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसी तरह, घाघरा नदी अयोध्या और एल्गिन ब्रिज (बाराबंकी) में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है।

राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर निशाना, वोट चोरी का डेटा किया सार्वजनिक

नई दिल्ली (एजेन्सी)।

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव का डेटा दिखाकर आरोप लगाया कि राज्य विधानसभा चुनाव में धांधली हुई है और 40 लाख वोट रहस्यमयी तरीके से जोड़े गए। कांग्रेस नेता ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अनियमितताओं का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 5 महीनों में लाखों मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े गए, जो काफी चिंताजनक है। नए मतदाताओं के जुड़ने से हमारा संदेह बढ़ा और फिर शाम 5 बजे के बाद मतदान में भारी बढ़ोतरी देखी गई।

लोकसभा चुनाव में हमारे गठबंधन की शानदार जीत हुई, लेकिन विधानसभा चुनाव में हमारे गठबंधन को पूरी तरह हार का सामना करना पड़ा, जो बहुत संदिग्ध है। राहुल गांधी ने कहा कि हमने अपनी जांच शुरू की। बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट की हार की जांच की गई खासकर महादेवपुरा विधानसभा में। यहां से बीजेपी को 1.14 लाख की लीड मिली, जबकि पूरे लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस सिर्फ 32,000 वोट से हारी। 7 फीट ऊंचे वोटर लिस्ट ढेर से 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी पकड़ी गई। कांग्रेस नेता ने कहा कि वोट चोरी के 5 प्रकार हमने निकाले।

राहुल गांधी ने बताया कि 'चुनाव धांधली' के सबूत एकत्र करने में कुल छह महीने का समय लगा है। राहुल गांधी ने दावा किया कि निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियों को मशीन के पढ़ने योग्य (मशीन रीडेबल) डेटा उपलब्ध नहीं करा रहा है ताकि ये सब पकड़ा नहीं जा सके। उनकी टीम ने बेंगलुरु मध्य लोकसभा सीट के महादेवपुरा

विधानसभा क्षेत्र के डेटा का विश्लेषण किया और फिर गड़बड़ी का पता किया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी बेंगलुरु मध्य लोकसभा सीट के सभी सात विधानसभा क्षेत्रों में छह में पिछड़ गई, लेकिन महादेवपुरा में उसे एकतरफा वोट मिला। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1,00,250 मतों की चोरी की गई। उन्होंने कहा कि एक पते पर 50-50 मतदाता थे। कई जगहों पर नाम एक थे, फोटो अलग अलग थे।

राहुल गांधी ने कहा कि हमारे विश्लेषण में पता चला कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच एक करोड़ नए मतदाता जुड़ गए। हमने इस मुद्दे को चुनाव आयोग के सामने उठाया और एक लेख लिखा, जिसमें हमारा मुख्य तर्क था कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया। कांग्रेस नेता ने कहा कि हर लोकतंत्र में सत्तारूढ़ पार्टी को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ता है, लेकिन भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है, जो इस लहर से प्रभावित नहीं होती।

खड़गे ने राहुल का किया समर्थन

नई दिल्ली (एजेन्सी)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) पर तीखा हमला करते हुए उस पर सत्तारूढ़ दल के प्रतिनिधि की तरह काम करने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के अपने संवैधानिक कर्तव्य में कथित रूप से विफल रहने का आरोप लगाया। खड़गे ने एक्स पर लिखा कि एक वक़्त था जब भारत के चुनाव आयोग की वाहवाही पूरे विश्व में होती थी। कितने ही देश हमारे चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराने की ट्रेनिंग लेते थे। जब कोई राजनीतिक दल चुनाव आयोग से सवाल पूछता था वो संविधान की मर्यादा के दायरे में उसका जवाब या स्पष्टीकरण देते थे। खड़गे ने आगे कहा कि आज जब कोई ECI से सवाल पूछता है तो वो जवाब नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के नुमायंदे की तरह उलटे इल्जाम लगाता है, विपक्षी पार्टियों की माँगों पर गौर किये बिना केवल अनर्गल बयानबाजी करता है। उन्होंने आगे कहा कि आज राहुल गांधी ने कर्नाटक की महादेवापुरा सीट के, गहन जाँच के बाद, उदहारण देकर, बताया कि किस तरह से चुनाव आयोग ने एक चुनाव में ही घोर धाँधली होने दी और अपने संवैधानिक कर्त्तव्य को तार-तार किया, जिसमें 1,00,250 वोटों की चोरी की गई।

दिल्ली की खेल क्रांति का शुभारंभः सीएम रेखा गुप्ता ने खेल और युवा मामलों के विशेष विभाग की घोषणा की

एसबी संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली की ओलिंपिक असोसिएशन, विभिन्न सरकारी विद्यालयों और खेल प्रशिक्षण केंद्रों से आए बच्चों ने आज दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा से मुलाकात की और राजधानी के युवा खिलाड़ियों और मेधावी छात्रों के लिए घोषित ऐतिहासिक पहलों के प्रति आभार प्रकट किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि दिल्ली में खेल और युवा मामलों के लिए अब अलग विभाग बनेगा, जिससे खिलाड़ियों को जरूरत के मुताबिक सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने यह भी कहा कि पूरी राजधानी में कोचिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे, ताकि कोई भी खिलाड़ी संसाधनों की कमी के कारण पीछे न रह जाए।

इस अवसर पर दिल्ली सरकार के खेल मंत्री श्री आशीष सूद भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने बच्चो से संवाद करते हुए कहा कि उनका सपना है कि दिल्ली का हर बच्चा आत्मनिर्भर, सशक्त और आत्मविश्वासी बने। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने सरकार की जिम्मेदारी

संभाली, तो यह महसूस हुआ कि दिल्ली के खिलाड़ी कड़ी मेहनत तो करते हैं, लेकिन उन्हें वह मान्यता, सहायता और सम्मान नहीं मिलती जिसके वे हकदार हैं। इसी को बदलने के उद्देश्य से उन्होंने देश की सबसे बड़ी इनामी राशि के साथ एक नई खेल नीति लागू की। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस नई नीति के तहत अब दिल्ली में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को सात करोड़ रुपये, रजत पदक विजेता को पांच करोड़ रुपये और कांस्य पदक विजेता को तीन करोड़ रुपये दिए जाएंगे। यह इनामी राशि देश के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सबसे अधिक है। इसके साथ ही खिलाड़ियों को ग्रेड ए, बी और सी की सरकारी नौकरियों में नियुक्ति का अवसर भी मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ये योजनाएँ सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि युवाओं के सपनों को उड़ान देने की नींव हैं। उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली सरकार द्वारा वर्षों से जर्जर पड़े स्टेडियमों का पुनर्निर्माण किया जाएगा और उन्हें अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ कोचिंग, संसाधन और हर संभव सहयोग दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि दिल्ली में खेल और युवा मामलों के लिए अब अलग विभाग बनेगा, जिससे खिलाड़ियों को जरूरत के मुताबिक सुविधाएं मिल सकें। साथ ही, पूरे शहर में कोचिंग सेंटर (क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र) स्थापित किए जाएंगे, ताकि किसी खिलाड़ी को संसाधनों की कमी के कारण पीछे न रहना पड़े। मुख्यमंत्री ने बच्चों से कहा कि उनका असली आभार तभी माना जाएगा जब वे देश के लिए जीत हासिल करेंगे, आगे बढ़ेंगे और दिल्ली को गर्व महसूस कराएंगे। उन्होंने बच्चों से यह संकल्प लेने का आह्वान किया कि अब जब दिल्ली सरकार ने इनाम तय कर दिए हैं, तो उन्हें यह राशि अपने परिश्रम से जीतकर दिखाना उनकी ज़िम्मेदारी है।

इस अवसर पर मंत्री श्री आशीष सूद ने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने यह साबित कर दिया है कि प्रतिभा को सिर्फ पहचाना ही नहीं, बल्कि उसे पूरी ताकत के साथ संवारना भी हमारी जिम्मेदारी है। यह नई खेल नीति और युवाओं के लिए अलग विभाग की घोषणा एक क्रांतिकारी कदम है, जो आने वाले वर्षों में दिल्ली को खेल और शिक्षा दोनों क्षेत्रों में देशभर में अग्रणी बनाएगा।

पूर्व सरकार ने जिन विकास योजनाओं पर प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा था, उन्हें दिल्ली में लागू नहीं कियाः रेखा गुप्ता

सीएजी रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति को सौंपी जाए-सीएम

संजना भारती संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में दिल्ली की पूर्व सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि पिछली सरकार ने अपनी मुफ्त योजनाओं को इस तरह पेश किया जैसे वे अपनी जेब से जनता को दे रहे हों, जबकि हकीकत यह है कि यह सारा पैसा जनता का ही था। जनता को उम्मीद थी कि उनके टैक्स के पैसे से सड़कें बनेंगी, स्कूल और अस्पताल बनेंगे, लेकिन उनकी मेहनत की कमाई को मुफ्त योजनाओं में खर्च कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पूर्व सरकार ने विकास कार्यों को जानबूझकर नजरअंदाज किया और सारा ध्यान केवल प्रचार-प्रसार पर केंद्रित रखा। मुख्यमंत्री का यह भी कहना था कि पिछली सरकार ने उन विकास कार्यों पर इसलिए खर्च नहीं किया गया क्योंकि उन योजनाओं में प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा था।

दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित वर्ष 2023-24 के वित्तीय लेखे व विनियोग लेखे) पर बोलते हुए मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने ब्यौरेवार पिछली सरकार (और अब विपक्ष) को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि सीएजी रिपोर्ट पिछली सरकार की कारगुजारियों और काम न करने की सोच

को उजागर करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें पहले से आशंका थी कि जैसे ही सीएजी रिपोर्ट सामने आएगी, विपक्ष या तो सदन से बाहर चला जाएगा या फिर सारा दोष केंद्र सरकार पर मढ़ने की कोशिश करेगा। वे यह कहेंगे कि उन्हें केंद्र सरकार से न तो कोई वित्तीय सहायता मिली और न ही कोई ग्रांट दी गई। लेकिन सच्चाई यह है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली को 4800 करोड़ रुपये की ग्रांट दी थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जानना जरूरी है कि इस राशि का उपयोग कैसे किया गया। 463 करोड़ रुपये पानी की आपूर्ति पर, 482 करोड़ रुपये फ्री बस सेवाओं पर और 3250 करोड़ रुपये फ्री बिजली योजना पर खर्च कर दिए गए। इस तरह पूरी ग्रांट को मुफ्त योजनाओं में वितरित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विपक्ष ने इन मुफ्त योजनाओं को इस तरह प्रस्तुत किया जैसे वे अपनी जेब से जनता को दे रहे हों, जबकि हकीकत यह है कि यह सारा पैसा जनता का ही था।

सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकार का पूरा राजस्व केवल खर्चों में चला गया। तनख्वाह, ब्याज भुगतान और अन्य ऐसे खर्च, जिनसे कोई स्थायी संपत्ति नहीं बनती। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022-23 में दिल्ली सरकार का राजस्व अधिशेष 4566 करोड़ रुपये था, लेकिन यह पूरा पैसा खर्च कर दिया गया।

प्रीमियम सुविधाओं वाली किफायती ट्रेनः अमृत भारत

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह सीतामढ़ी से दिल्ली के लिए साप्ताहिक अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना

संजना भारती/विज्ञप्ति द्वारा

सीतामढ़ी। बैरगनिया रक्सौल सिकटा नरकटियागंज और बगहा के लोगों को भारतीय रेल से बड़ी सौगात मिलने वाली है। रेल सूत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को बिहार की यात्रा पर आएंगे तो सीतामढ़ी से हरी झंडी दिखाकर सीतामढ़ी से दिल्ली के लिए साप्ताहिक अमृत भारत ट्रेन को रवाना करेंगे।

भारतीय रेल की ओर से बिहार को मिलने वाली यह सातवीं अमृत भारत ट्रेन है। इससे पहले जब देश में पहली बार अमृत भारत ट्रेनें बनकर तैयार हुई थी, तो उनका परिचालन दरभंगा से वाया अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल तथा मालदा टाउन से सर एम. विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरू के बीच किया गया था। सहरसा और मुंबई अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन भी मोदी जी के द्वारा हरी झंडी दिखाई जाने के बाद किया गया। इसके अलावा पटना और नई दिल्ली के बीच दैनिक अमृत भारत एक्सप्रेस के साथ-साथ मोतिहारी से आनंद विहार के लिए और दरभंगा तथा मालदा टाउन से भाया भागलपुर, गया, सासाराम लखनऊ के लिए अमृत भारतीय एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है जिससे बिहार के लोगों को काफी लाभ मिल रहा है।

अमृत भारत ट्रेनों का निर्माण मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री में किया गया है। इसे खास तौर पर मध्य एवं निम्न आय वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसमें स्लीपर और जनरल क्लास के डिब्बे लगे हुए हैं। आधुनिक सुविधाओं से लैस अमृत भारत ट्रेन के नए संस्करण

में कई-नई सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं, जिससे अमृत भारत 2.0 पहले से कहीं ज्यादा सुविधाजनक और हाईटेक हो गई है। अमृत भारत ट्रेन लो बजट में यात्रा करने का एक सुविधाजनक और विश्वसनीय माध्यम बन गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में जानकारी दी थी कि देश में 100 नए अमृत भारत रेक निमार्णाधीन हैं, जिन्हें भारतीय रेल के विभिन्न रूटों पर चलाया जाएगा।

विदित हो कि अमृत भारत 2.0 ट्रेन के कोच में फोल्डेबल स्नैक्स टेबल, मोबाइल होल्डर, फोल्डेबल बॉटल होल्डर जैसी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इनमें हवाई जहाज की तर्ज पर रेडियम एलिमिनेटेड फ्लोरिंग स्ट्रिप, एयर स्प्रिंग बॉडी जैसी सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिससे सफर आरामदायक होता है।

इस ट्रेन के प्रत्येक शौचालय में इलेक्ट्रो न्यूमेटिक फ्लशिंग प्रणाली, ऑटोमेटिक सॉप डिस्पेंसर और एरोसॉल आधारित फायर सप्रेशन सिस्टम लगाया गया है, जिससे स्वच्छता और सुरक्षा को मजबूती प्राप्त होगी। शौचालयों के निर्माण में शीट मेटल कंपाउंड सामग्री का उपयोग किया गया है जिससे रखरखाव आसान होगा। अमृत भारत 2.0 ट्रेन में 130 किमी/ घंटा रफ्तार देने की क्षमता है। भारतीय रेल के इतिहास में पहली बार ट्रेन में सेमी-ऑटोमैटिक कपलर का उपयोग किया गया है, जो न केवल यात्रा को सुगम बनाती है, बल्कि कनेक्शन को भी सुविधाजनक बनाती है।

लोकोमोटिव के साथ यह रेक स्थिरता के साथ उच्चतम गति और बेहतर संचालन सुनिश्चित करता है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कपलर में क्रैश ट्यूब और EP-असिस्टेड ब्रेक सिस्टम की सुविधा दी गई है, जिससे तेजी से ब्रेक लग सकेगा। ये फीचर पहली बार भारतीय ट्रेनों में जोड़ा गया है। इसके अलावा पूरी तरह से सील गैंगवे और वैक्यूम एवैक्यूशन सिस्टम से लैस है।

यात्री और सुरक्षा-गार्ड के बीच दो-तरफा संचार के लिए प्रत्येक कोच में इमरजेंसी टॉक बैक सिस्टम की नई सुविधा जोड़ी गई है। गैर-एसी कोचों में पहली बार फायर डिटेक्शन सिस्टम की सुविधा यात्रियों की सुरक्षा में नई क्रांति है।

ऑन-बोर्ड कंडीशन मॉनिटरिंग सिस्टम से रियल टाइम व्हील और बियरिंग की निगरानी होती है। इंटरनेट आधारित वाटर लेवल इंडिकेटर स्टेशनों और ऑन-बोर्ड स्टाफ को सहायता प्रदान करते हैं। देश में पहली बार किसी ट्रेन में बाहरी आपातकालीन लाइट्स की सुविधा भी दी गई है।

सीतामढ़ी-दिल्ली-सीतामढ़ी नई अमृत भारत साप्ताहिक एक्सप्रेस चलाई जायेगी, जिसका शुभारम्भ 08 अगस्त, 2025 शुक्रवार को 05599 सीतामढ़ी-दिल्ली उद्घाटन विशेष गाड़ी के रूप में किया जायेगा। यह गैर-वातानुकूलित श्रेणी की प्रीमियम ट्रेन है।

05599 सीतामढ़ी-दिल्ली उद्घाटन विशेष गाड़ी 08 अगस्त, 2025 शुक्रवार को सीतामढ़ी से 14.30 बजे प्रस्थान कर बैरगनिया से 15.20 बजे, रक्सौल से 16.15 बजे, नरकटियागंज से 17.20 बजे, बगहा से 18.25 बजे, सिसवा बाजार से 20.00 बजे, कप्तानगंज से 20.35 बजे, गोरखपुर से 21.40 बजे, बस्ती से 22.50 बजे, दूसरे दिन गोंडा से 00.40 बजे, लखनऊ (उत्तर रेलवे) से 03.45 बजे, कानपुर सेंट्रल से 06.05 बजे, टूण्डला से 09.15 बजे तथा गाजियाबाद से 12.20 बजे छूटकर दिल्ली 14.00 बजे पहुँचेगी।

इस उद्घाटन विशेष गाड़ी में एल.एस.एल.आर.डी. के 02, सामान्य द्वितीय श्रेणी के 11, शयनयान श्रेणी के 08 तथा पैंट्रीकार के 01 कोच सहित कुल 22 कोच लगाये जायेंगे।

एसआईआर पर जारी है विपक्ष का हंगामा

नई दिल्ली (एजेन्सी)। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी इंडिया ब्लॉक के हंगामे के बीच गुरुवार को लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई। हालाँकि, केंद्र सरकार ने यह कहते हुए इस मांग को खारिज कर दिया कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। बावजूद इसके विपक्ष का हंगामा जारी रहा। विपक्षी सदस्यों द्वारा लगातार विरोध व्यवधान के बाद लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी ठीक ऐसी ही स्थिति रही। यहां भी विपक्ष के हंगामे के बाद कार्यवाही को दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के बीच मणिपुर वस्तु और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 और मणिपुर विनियोग विधेयक, 2025 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन पर निशाना साधते हुए कहा, मणिपुर के लिए घड़ियाली आंसू बहाने वाले विपक्षी दल मणिपुर के हित में जो पैसा जा रहा है, उसके खिलाफ बोल रहे हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को लोकसभा को बताया कि इस साल नियामक और भू-राजनीतिक मुद्दों के कारण विमानन कंपनियों ने 2,458 उड़ानें रद्द या पुनर्निर्धारित कीं। नागर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि देरी और रद्द होने के कारण विमानन कंपनियों को अतिरिक्त ईंधन, चालक दल का अतिरिक्त समय, रखरखाव, हवाई अड्डा शुल्क और पुनः बुकिंग खर्च सहित विभिन्न लागत उठानी पड़ती हैं।

नायब सिंह सैनी ने जिला सिविल अस्पतालों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

एसबी संवाददाता

चंडीगढ़। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सिविल अस्पतालों के आधुनिकीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए इन अस्पतालों को निजी स्वास्थ्य सुविधाओं के मानकों के अनुरूप उन्नत करने के लिए एक परिवर्तनकारी पहल शुरू की है। यह पहल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा की गई बजट घोषणा को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम है। यह दूरदर्शी प्रयास सिविल अस्पतालों के बुनियादी ढाँचे के नवीनीकरण पर केंद्रित है, जिसमें शौचालय की मरम्मत से लेकर सफेदी और रंग-रोगन शामिल है। इसका उद्देश्य रोगियों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करवाना है।

यह जानकारी यहाँ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित में जिला सिविल अस्पतालों की समीक्षा बैठक में दी गई। बैठक में बताया गया कि पंचकूला, जींद, गुरुग्राम, कैथल, मांडीखेड़ा (नूंह), रेवाड़ी, सिरसा और कुरुक्षेत्र सहित 8 सिविल अस्पतालों में विशेष मरम्मत और नवीनीकरण का कार्य शुरू हो चुका है। इसके अलावा, अंबाला,

सिविल अस्पतालों को उन्नत उपचार सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है-मुख्यमंत्री नायब सैनी

भिवानी, पलवल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, नारनौल, फतेहाबाद, फरीदाबाद, रोहतक, हिसार और चरखी दादरी सहित 13 जिला अस्पतालों में भी जल्द ही कार्य शुरू किया जाएगा। इस योजना के तहत बिजली की मरम्मत, बेहतर लाइटिंग व्यवस्था और रोगी देखभाल तथा कर्मचारियों की कार्यकुशलता में सुधार के लिए विश्वसनीय एयर कंडीशनिंग आदि आवश्यक सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण शामिल है।

आंतरिक सड़कों की मरम्मत और अस्पताल के संकेतों को ठीक करने जैसे व्यावहारिक सुधारों से आवागमन आसान होगा और आगंतुकों और स्वास्थ्य कर्मियों, दोनों के लिए एक बेहतर वातावरण तैयार होगा। अस्पताल भवनों के सुधारीकरण के साथ-साथ अग्निशमन सुविधाओं को मजबूत किया जायेगा। इसके अलावा बागवानी सुधारों के माध्यम से अस्पताल परिसरों में हरियाली लाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने सदन में राज्य भर के सभी सिविल अस्पतालों के आधुनिकीकरण और उन्हें मरीजों के लिए आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने की घोषणा की है। उन्होंने राज्य सरकार की इस प्रतिबद्धता पर जोर दिया कि सिविल अस्पतालों में आने वाले हर मरीज को सभी जरूरी सेवाएँ मिलें। उन्होंने कहा कि सभी सिविल अस्पतालों को उन्नत उपचार सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है ताकि लोगों को इलाज के लिए निजी अस्पतालों में न जाना पड़े।

मुख्यमंत्री ने ज़िला अस्पतालों में मरीजों के लिए उपलब्ध सेवाओं की भी समीक्षा की, जिनमें निजी कक्ष, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, स्वचालित प्रयोगशालाएँ, ब्लड बैंक और एक्स-रे शामिल हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि मरीजों को निर्बाध सेवाएँ प्रदान करने के लिए सभी मशीनों को अच्छी स्थिति में रखा जाए। उन्होंने इन मशीनों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

सम्पादकीय

ट्रंप का टैरिफ वॉर

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी धमकी के मुताबिक, भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। इस नए ऐलान के बाद भारत पर अब कुल मिलाकर अमेरिका ने 50 प्रतिशत का टैरिफ लगा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जिद का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने दुनिया पर सबसे ज्यादा टैरिफ भारत पर थोप दिया है। ट्रंप के ऐलान के बाद दुनिया के दो देशों- भारत और ब्राजील पर सबसे ज्यादा टैरिफ (50 प्रतिशत) लग गया है। ट्रंप का यह फैसला अपने आप में कितना अजीब है कि रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाले देश चीन पर उसने सिर्फ 30 प्रतिशत का ही टैरिफ लगाया है, जबकि भारत पर 50 प्रतिशत थोप दिया है। ऐसे में अब सवाल यह उठ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस जिद भरे फैसले को कैसे देखा जाए क्योंकि अमेरिका इस बात को बखूबी समझता है कि भारत की कोई भी सरकार अमेरिका के दबाव में रूस के साथ अपने कारोबारी रिश्ते को खत्म नहीं कर सकती है। भारत रूस से तेल भी खरीदता रहेगा और व्यापारिक संबंध भी रखेगा। ऐसे में कई जानकारों का यह भी मानना है कि ट्रंप का यह फैसला बातचीत से पहले भारत पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है। याद दिला दें कि, भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते और टैरिफ को लेकर बातचीत लगातार जारी है और छठे दौर की बातचीत के लिए अमेरिकी अधिकारियों का एक दल 25 अगस्त को भारत के दौरे पर आने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति के ऐलान के बाद, भारत ने बुधवार को ही इसका जवाब भी दे दिया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बुधवार को ही अमेरिका के फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए बयान जारी कर कहा कि,"हाल के दिनों में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस से भारत के तेल आयात को निशाना बनाया है। हमने इन मुद्दों पर अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि हमारे आयात बाजार के कारकों पर आधारित हैं और भारत के 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के समग्र उद्देश्य से किए जाते हैं। इसलिए, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ने भारत पर उन कार्यों के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाने का विकल्प चुना है जो कई अन्य देश भी अपने राष्ट्रीय हित में कर रहे हैं।" भारत ने अपने बयान में अमेरिकी फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए आगे स्पष्ट तौर पर कहा, "हम दोहराते हैं कि ये कार्य अनुचित और अविवेकपूर्ण हैं। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।" प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को स्वयं मोर्चा संभालते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सख्त संदेश देने का भी प्रयास किया।आईसीएआर पूसा में आयोजित एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरे भाई-बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशु पालकों के लिए आज भारत तैयार है।" इन तमाम बयानों से यह साफ-साफ नजर आ रहा है कि टैरिफ की यह लड़ाई लंबी खिंचने वाली है। ऐसे में समय की यह मांग कि है भारत अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करने के साथ-साथ अमेरिका को एक बड़ा झटका भी देने की तरफ बढ़े और यह वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों से ही संभव हो सकता है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने पहले ही डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका देते हुए यह कह दिया है कि, वह टैरिफ पर बात करने के लिए ट्रंप को कॉल नहीं करेंगे। इसकी बजाय वह भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग जैसे नेताओं के साथ बातचीत करना चाहेंगे। भारत को भी इसी तरह का सख्त स्टैंड लेते हुए बातचीत करने के लिए 25 अगस्त को आ रहे अमेरिकी अधिकारियों का दौरा रद्द कर देना चाहिए। इसी महीने के अंत में जापान और चीन की यात्रा पर जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीन, रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और जापान के साथ मिलकर डोनाल्ड ट्रंप को सबक सिखाने की रणनीति बनाने पर काम करना चाहिए। लेकिन ऐसा करते समय, चीनी राष्ट्रपति को यह स्पष्ट तौर पर बता भी देना चाहिए कि ऐसे मौके का फायदा उठाकर अगर चीन की सेना ने भारत-चीन सीमा पर कोई नापाक हरकत की तो इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत के लिए सही मायनों में यह आपदा में अवसर का प्रतीक है और अगर हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सही तरीके से अपना दांव चला तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं पाएगा।

जयंती

भीष्म साहनी

जन्म-8 अगस्त, 1915, रावलपिण्डी, अविभाजित भारत; मृत्यु-11 जुलाई, 2003, दिल्ली) प्रसिद्ध भारतीय लेखक थे। उन्हें हिन्दी साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है। वे आधुनिक हिन्दी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। भीष्म साहनी मानवीय मूल्यों के सदैव हिमायती रहे। वामपंथी विचारधारा से जुड़े होने के साथ-साथ वे मानवीय मूल्यों को कभी आंखों से ओझल नहीं करते थे। आपाधापी और उठापटक के युग में भीष्म साहनी का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग था। उन्हें उनके लेखन के लिए तो स्मरण किया ही जाता है, लेकिन अपनी सहृदयता के लिए भी वे चिरस्मरणीय हैं। भीष्म साहनी ने कई प्रसिद्ध रचनाएँ की थीं, जिनमें से उनके उपन्यास 'तमस' पर वर्ष 1986 में एक फि ल्म का निर्माण भी किया गया था। उन्हें कई पुरस्कार व सम्मान प्राप्त हुए थे। 1998 में भारत सरकार के 'पद्म भूषण' अलंकरण से भी वे विभूषित किये गए थे।

पुण्यतिथि

अनुपम श्याम

जन्म-20 सितम्बर, 1957; मृत्यु-8 अगस्त, 2021) भारतीय फिल्म व टीवी कलाकार थे, जो कि मुख्य तौर से हिंदी सिनेमा और टीवी जगत में सक्रिय रहे। अनुपम श्याम ने वैसे तो कई फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में अभिनय किया, लेकिन उन्हें असली सफलता मिली साल 2009 में आए टीवी सीरियल 'मन की आवाज प्रतिज्ञा' से। इस सीरियल में अनुपम श्याम ने ठाकुर सज्जन सिंह का किरदार निभाया था। यह टीवी सीरियल लोगों को खूब पसंद आया और खासकर अनुपम श्याम का किरदार। इसके बाद वह घर-घर में पहचाने जाने लगे थे।

कल मिलेंगे

एक बार सोनू की पत्नी बीमार थी
सोनू-बेबी अगर आप मर गईं तो मैं भी मर जाऊंगा.
पत्नी-मैं तो बीमार हूं, तुम क्यों मरोगे?
सोनू-खुशी से...

संजना भारती दैनिक

भगवान शंकर जी के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी (मेंहदीपुर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में श्रद्धापूर्वक समर्पित है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक-**संजय कुमार** द्वारा आर.डी. प्रिंटर एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-41, सेक्टर-8, नोएडा, उत्तर प्रदेश से मुद्रित तथा ए-281सी, गली नं. 3, ए-ब्लॉक, अम्बिका विहार, शिव विहार, दिल्ली-110094 से प्रकाशित। इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी।

RNI No. : DELHIN/2016/70240

Phone No.: 9871221635

E-mail ID: sanjanabharati16@gmail.com

(किसी भी वाद-विवाद में न्याय क्षेत्र दिल्ली ही होगा।)

वोट बैंक के लालच ने बर्बाद किया हिमाचल-उत्तराखंड को

कोर्ट ने भाखड़ा और नाथपा झाकड़ी जैसे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना सही भूगर्भ जांच और पर्यावरण अध्ययन के ये प्रोजेक्ट्स पहाड़ों को कमजोर कर रहे हैं। न्यूनतम जल प्रवाह का पालन न होने से नदियों में जलीय जीवन खत्म हो रहा है। आज सतलुज नदी एक नाले जैसी हो गई है। कोर्ट ने साफ किया कि अब समय रहते सख्त कदम न उठाए गए तो हिमाचल का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है

-योगेन्द्र योगी

लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए दूरदृष्टि के साथ दूरगामी विकास को सिरे चढ़ाया जाए। इसके विपरीत नेताओं को सिर्फ वोट बैंक की चिंता है। इसके लिए तात्कालिक विकास की नीतियों के फायदे के लिए लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने के साथ ही पर्यावरण के विनाशकारी प्रभावों की अनदेखी करना आम है। यही वजह है कि हिमाचल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ी लताड़ लगाई है। कोर्ट ने कहा कि अगर अनियंत्रित विकास और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियां नहीं रोकी गईं, तो एक दिन पूरा हिमाचल नक्शे से गायब हो सकता है। यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब हिमाचल में बदलते पर्यावरण को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं और विकास के नाम पर अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट की इस कड़ी टिप्पणी के अगले ही दिन उत्तराखंड के चमोली में चमोली जिले में हेलंग के समीप निमार्णाधीन एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइट के पास पहाड़ एक बार फिर से ढहकर धड़ाम से नीचे गिर गया। इस हादसे में कंपनी के 8 मजदूर घायल हो गए। साइट पर हादसे के वक्त करीब 300 मजदूर थे। जहां पर लैंडस्लाइड हुआ वहां पर 70 के करीब मजदूर कार्य कर रहे थे। ऐसे हादसों के बावजूद हिमालयी क्षेत्र के राज्यों की सरकारों ने कोई सबक नहीं सीखा है। इन राज्यों में विकास के नाम पर बबार्दी की कहानी लिखी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि कहा कि सरकारों का मकसद राजस्व बढ़ाना नहीं बल्कि पर्यावरण को बचाना होना चाहिए खासकर ऐसे संवेदनशील इलाकों में। कोर्ट ने यह टिप्पणी एक होटल कंपनी की याचिका खारिज करते हुए की। यह कंपनी जून 2025 की उस अधिसूचना के खिलाफ थी, जिसमें हिमाचल के श्री तारा माता हिल को ग्रीन एरिया घोषित कर नई प्राइवेट कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई थी। बेंच ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इस साल भी बाढ़ और भूस्खलन में सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घर तबाह हो गए। यह साफ है कि प्रकृति इंसानी गतिविधियों से नाराज है। कोर्ट ने आगे कहा कि केवल प्रकृति को दोष देना गलत है। हिमाचल में पहाड़ों का खिसकना, सड़कों पर लैंडस्लाइड, मकानों का गिरना और सड़क धंसना, ये सब इंसानों की छेड़छाड़ का नतीजा है।

कोर्ट ने भाखड़ा और नाथपा झाकड़ी जैसे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना सही भूगर्भ जांच और पर्यावरण अध्ययन के ये प्रोजेक्ट्स पहाड़ों को कमजोर कर रहे हैं। न्यूनतम जल प्रवाह का पालन न होने से नदियों में जलीय जीवन खत्म हो रहा है। आज सतलुज नदी एक नाले जैसी हो गई है। कोर्ट ने साफ किया कि अब समय रहते सख्त कदम न उठाए गए तो हिमाचल का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। गौरतलब है कि पिछले एक सदी में हिमाचल प्रदेश में औसत तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। यह जलवायु परिवर्तन का एक स्पष्ट संकेत है, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में आपदाओं की संख्या में तापमान में वृद्धि के कारण, बारिश की तीव्रता और आवृत्ति में वृद्धि हुई है, जिससे बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाएँ आ रही हैं। हिमाचल के पांच जिले (चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी) भूकंप के लिए अति संवेदनशील क्षेत्र में आते हैं। भूकंप और लगातार बारिश से पहाड़ कमजोर हो जाते हैं, जिससे भूस्खलन की घटनाएं बढ़ती हैं। हिमाचल में लगभग 58.36 प्रतिशत भूमि तीव्र मिट्टी कटाव के खतरे में है। भारी बारिश के कारण मिट्टी बह जाती है, जिससे पहाड़ों की स्थिरता कम होती है और भूस्खलन का खतरा बढ़ता है। हिमाचल में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इससे नदियों में पानी का स्तर बढ़ जाता है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ता है। हिमाचल में अनियोजित-अवैज्ञानिक विकास कार्यों ने आपदाओं को और बढ़ावा दिया है।

विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार और डेवलपर्स पर्यावरणीय प्रभावों को नजरअंदाज कर रहे हैं। हिमाचल में 174 छोटे-बड़े हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स हैं, जो 11,209 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। इन प्रोजेक्ट्स के लिए पहाड़ों को काटा जाता है। नदियों का प्रवाह बाधित होता है। वर्ष 2023 में कुल्लू और सैंज वैली में मलाना, सैंज और पार्वती प्रोजेक्ट्स के पास भारी नुकसान हुआ। मंडी, कुल्लू और शिमला में सड़क निर्माण के कारण बारिश में स्लिप और भूस्खलन की घटनाएं आम हैं। शिमला जैसे शहरों में बहुमंजिला इमारतें बन रही हैं, जो पर्यावरणीय चेतावनियों को नजरअंदाज करती हैं। हिमाचल में जंगलों को काटकर बिजली प्रोजेक्ट्स, सड़कों और पर्यटन के लिए जगह बनाई जा रही है।

वर्ष 1980 से 2014 तक किन्नौर में 90 प्रतिशत जंगल गैर-वन गतिविधियों के लिए हस्तांतरित किए गए, जिससे जैव विविधता और मिट्टी की स्थिरता को नुकसान हुआ। हिमाचल में हर साल लाखों पर्यटक आते हैं, खासकर कुल्लू, मनाली और शिमला जैसे क्षेत्रों में। इससे पर्यावरण पर दबाव बढ़ता है। होटल, रिसॉर्ट्स और अन्य निर्माण कार्यों के लिए पहाड़ों को काटा जाता है। कचरे का उचित प्रबंधन नहीं होता। इससे जल स्रोत और नदियां प्रदूषित होती हैं। बाढ़ जैसी स्थिति बनती है। पिछले कुछ सालों में हिमाचल में आपदाओं की संख्या और तीव्रता बढ़ी है। वर्ष 2021 में 476 लोगों की मृत्यु और करीब 1151 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। वर्ष 2022 में 276 लोगों की मृत्यु और 939 करोड़ रुपये का नुकसान, वर्ष 2023 में 404 लोगों की मृत्यु तथा 12000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इसी तरह पिछले वर्ष 2024 में 358 लोगों की मृत्यु, 1004 घर क्षतिग्रस्त, और 7088 पशु हानि और 18 बादल फटने की घटनाओं ने 14 हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचाया। कमोबेश ऐसे ही विनाशकारी हालात उत्तराखंड के हैं। इस साल भी बारिश के कारण उत्तराखंड में एक जून से लेकर अभी तक प्राकृतिक आपदाओं में 25 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड में नदियां अक्सर भारी बारिश के कारण उफान पर आ जाती हैं, जिससे बाढ़ और भूस्खलन होता है। वर्ष 2013 की केदारनाथ आपदा में मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ ने व्यापक विनाश किया था। वर्ष 2021 में उत्तराखंड में 17 प्रमुख बादल फटने की घटनाएं हुईं। जिससे 34 लोगों की मौत हो गई और 106 घर दब गए। आश्चर्य यह है कि इन दोनों राज्यों की सरकारों ने इन प्राकृतिक आपदाओं से कोई सबक नहीं सीखा। दोनों राज्यों में विकास के नाम अदूरदर्शी प्रतिकूल पर्यावरणीय गतिविधियां जारी हैं। इससे जाहिर है कि नेताओं की नजरें सिर्फ वोट बैंक तक सीमित रहती हैं, लोगों की जान-माल की यदि परवाह होती तो दोनों राज्यों के हालात इतने बदतर नहीं होते।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

रक्षाबंधन 2025: नारी रक्षा का संकल्प, एक सामाजिक चेतना

रक्षाबंधन आज सिर्फ पारंपरिक पर्व नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक आंदोलन जैसा है। लेकिन दुख इस बात का है कि इस पर्व की आत्मा धीरे-धीरे खोती जा रही है। आज बहनों के लिए यह पर्व सजने-संवरने और उपहार पाने का माध्यम बनता जा रहा है, जबकि भाइयों के लिए यह केवल एक औपचारिकता बनकर रह गया है। राखी के धागों की वह पवित्रता, भावनाओं की वह गहराई, अब कम होती जा रही है

-ललित गर्ग

भारत की सांस्कृतिक परंपराओं और त्योहारों की भूमि पर रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है जो केवल भाई-बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज में आत्मीयता, कर्तव्यबोध, और नैतिक मूल्यों के पुनर्संवेदन का पर्व है। यह पर्व नारी अस्मिता, समानता, सुरक्षा और प्रेम की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। राखी का धागा जितना कोमल दिखता है, उतनी ही उसमें गहराई और दृढ़ता होती है, यह एक ऐसा लौकिक बंधन है, जो प्रेम, आदर्शों और जिम्मेदारियों से बंधा होता है। रक्षाबंधन कोई साधारण पर्व नहीं, यह आदर्शों का हिमालय है, संकल्पों का सोपान है। यह पर्व सिर्फ भाई-बहन के प्रेम की रस्म नहीं, बल्कि पुरुष समाज द्वारा नारी को आश्वस्त करने, उसका मान-सम्मान बनाए रखने की शपथ का दिन है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि नारी केवल स्नेह की पात्र नहीं, वह शक्ति, श्रद्धा और समाज की दिशा तय करने वाली एक सशक्त प्रेरणा भी है।

आज जब महिलाएं समाज के हर क्षेत्र में बुलंदियों को छू रही हैं, सेना से लेकर विज्ञान, शिक्षा से लेकर खेल तक तब रक्षाबंधन उन्हें केवल भावनात्मक सुरक्षा नहीं, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सम्मान दिलाने का भी माध्यम बनता है। रक्षाबंधन की महत्ता को समझने के लिए उसके ऐतिहासिक संदर्भों को जानना आवश्यक है। भविष्य पुराण में उल्लिखित कथा के अनुसार जब देव-दानव युद्ध में दानव भारी पड़ने लगे, तब इंद्राणी ने अपने पति इन्द्र की रक्षा हेतु रेशम का धागा मंत्रों के साथ उनके हाथ पर बांधा, जिससे इंद्र विजयी हुए। मुगल काल में रानी कर्मवती ने जब चितौड़ पर संकट देखा, तो बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर रक्षा की याचना की। हुमायूं ने धर्म, संप्रदाय और सत्ता से ऊपर उठकर उस धागे की लाज रखी और चितौड़ की रक्षा में अपनी ताकत झोंक दी। महाभारत में जब भगवान श्रीकृष्ण की उंगली से रक्त बहा, द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर पट्टी बांध दी। श्रीकृष्ण ने उस प्रेम को जीवन भर निभाया और चीरहरण के समय द्रौपदी की रक्षा की। यह केवल ऋण चुकता नहीं था, यह आदर्शों की प्रतिज्ञा थी। इसी तरह सिकंदर और पुरू की कथा इस बात को दर्शाती है कि राखी का एक धागा युद्ध भूमि में भी जीवनदान का कारण बन सकता है। ये प्रसंग हमें बताते हैं कि राखी केवल प्रेम का प्रतीक नहीं, बल्कि रक्षा, आदर्श और सम्मान की जीवंत प्रतिमा है।

रक्षाबंधन आज सिर्फ पारंपरिक पर्व नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक आंदोलन जैसा है। लेकिन दुख इस बात का है कि इस पर्व की आत्मा धीरे-धीरे खोती जा रही है। आज बहनों के लिए यह पर्व सजने-संवरने और उपहार पाने का माध्यम बनता जा रहा है, जबकि भाइयों के लिए यह केवल एक औपचारिकता बनकर रह गया है। राखी के धागों की वह पवित्रता, भावनाओं की वह गहराई, अब कम होती जा रही है। यह पर्व अब बाजारवाद और दिखावे के जाल में उलझता नजर आ रहा है। इस बदलती सोच को थामना और मूल भावनाओं को पुनः प्रतिष्ठित करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस पर्व का मूल उद्देश्य नारी के प्रति श्रद्धा, सुरक्षा और कर्तव्य का निर्वहन है, न कि केवल उपहार और दिखावे का आदान-प्रदान। भाइयों को चाहिए कि वे बहन की रक्षा की शपथ केवल शब्दों में नहीं, जीवन के प्रत्येक व्यवहार में निभाएं। बहनें भी राखी को केवल संबंध या औपचारिकता न समझें, बल्कि इस पर्व को नारी स्वाभिमान और सामाजिक बदलाव के एक माध्यम के रूप में लें।

आज जब समाज में महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं, जब बच्चियों से लेकर वृद्धाओं तक को भय और असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है, तब रक्षाबंधन एक ऐसा अवसर है जब हम केवल बहन नहीं, संपूर्ण नारी समाज की रक्षा का संकल्प लें। एक ऐसा संकल्प जो केवल राखी तक सीमित न हो, बल्कि जीवन भर के आचरण में झलके। यह पर्व हमें यह संदेश देता है कि नारी केवल स्नेह की नहीं, सम्मान की अधिकारिणी है। रक्षाबंधन भारत के विभिन्न अंचलों में अलग-अलग नामों से मनाया जाता है। उत्तर भारत में यह भाई-बहन के रिश्ते का पर्व है, वहीं महाराष्ट्र में नारली पूर्णिमा के रूप में समुद्र देवता को नारियल अर्पण कर मछुआरे समुद्र से अपने रिश्ते की रक्षा की प्रार्थना करते हैं। दक्षिण भारत में अवनी अविट्टम के रूप में यह ब्राह्मणों का यज्ञोपवीत संकल्प का पर्व है। वहीं स्कन्द पुराण और श्रीमद्भागवत में उल्लिखित वामन अवतार की कथा में रक्षाबंधन को बलेव के रूप में जाना जाता है, जब भगवान विष्णु ने तीन पग भूमि मांगकर राजा बलि का अभिमान तोड़ा था। इन सब कथाओं में एक ही संदेश है-अहंकार के स्थान पर समर्पण, दंभ के स्थान पर रक्षा, और स्वार्थ के स्थान पर सेवा।

आज रक्षाबंधन जैसे भावनात्मक और सांस्कृतिक पर्व भी कृत्रिम बुद्धिमता एवं संचार-क्रांति की आंधी में अपनी मूल आत्मा और संवेदना खोते जा रहे हैं। उपहारों की होड़, ब्रांडेड राखियों का प्रदर्शन, सोशल मीडिया पर दिखावे की होड़ ने इस पर्व को एक उपभोक्तावादी उत्सव में बदल दिया है। जहाँ पहले राखी एक भावनात्मक संबंध का प्रतीक थी, वहीं आज यह अधिकतर लेन-देन और औपचारिकता का माध्यम बनती जा रही है। इस प्रवृत्ति से पर्व की आत्मा, जिसमें बहन के प्रेम और भाई की जिम्मेदारी का गहन बोध निहित था, वह पीछे छूटता जा रहा है। इसलिए आवश्यक है कि हम रक्षाबंधन की प्रासंगिकता को केवल उपहारों और खर्च की दृष्टि से नहीं, बल्कि नारी सम्मान, आत्मीय रिश्तों और सामाजिक जिम्मेदारियों के दृष्टिकोण से समझें और मनाएं।

राखी का पर्व हमें मानवीय रिश्तों की फिर से व्याख्या करने का अवसर देता है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि हर स्त्री हमारी बहन है, समाज की, संस्कृति की, मानवता की। उसकी रक्षा केवल सामाजिक कर्तव्य नहीं, बल्कि मानवीय धर्म है। जब हर पुरुष स्त्री के प्रति अपने कर्तव्य को राखी की तरह पवित्र समझेगा, जब हर बहन अपने भाई में केवल उपहार देने वाला नहीं, बल्कि एक मूल्य-धारी रक्षक देखेगी, तब रक्षाबंधन केवल एक पर्व नहीं, एक क्रांति का आरंभ बनेगा। रक्षाबंधन कोई मंच या मंचन नहीं है। यह प्रदर्शन का नहीं, आत्मचिंतन का पर्व है। हमें इस पर्व को बाजारवाद और औपचारिकता से निकालकर पुनः उसकी असली पहचान देना होगा। यह प्रेम और कर्तव्य के बीच की एक खूबसूरत कड़ी है। इस बार राखी के धागों को केवल कलाई तक न सीमित रखें, इन्हें हृदय से बाँधें, ताकि यह पर्व भाई-बहन के रिश्तों से आगे बढ़कर पूरे समाज में एक सशक्त और सुरक्षित वातावरण का निर्माण कर सके। तभी राखी के ये धागे सच्चे अर्थों में आदर्श बनेंगे और संकल्पों का सोपान।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

खेल/विदेश/कारोबार/फिल्म

तुम एक इंच दोगे, वो एक मील ले लेगा, भारत पर टैरिफ से भड़के चीन ने ट्रंप को बताया बुली

(एजेन्सी)। **नई** दिल्ली में चीन के राजदूत शू फेइहोंग ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की। इससे एक दिन पहले ही ट्रंप ने रूस के साथ भारत के निरंतर तेल व्यापार के विरोध में भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगाया था, जिससे कुल ड्यूटी 50 प्रतिशत हो गई। डोनाल्ड ट्रम्प पर तीखा प्रहार करते हुए जू फेइहोंग ने उन्हें धमकाने वाला बताया। राजदूत ने बिना किसी का नाम लिए लिखा, धमकाने वाले को एक इंच दे दो, वह एक मील ले लेगा। उन्होंने चीनी विदेश मंत्री वांग यी और ब्राजील के राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार के बीच हाल ही में हुई फोन कॉल का एक अंश भी साझा किया। बातचीत में, यी ने कथित तौर पर कहा कि अन्य देशों को दबाने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों को कमजोर करता है। उत्तरवर्ती अमेरिकी प्रशासनों ने भारत को एक ऐसे प्रमुख साझेदार के रूप में देखा है जिसके चीन के संबंध में समान विचारधारा वाले हित हैं। भारत और चीन दक्षिण एशिया में रणनीतिक प्रभाव के लिए एक-दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंद्वी हैं। खबरों के अनुसार, मोदी अगस्त के अंत में अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी चीन की यात्रा कर सकते हैं। अधिकारियों ने इस यात्रा की पुष्टि नहीं की है, लेकिन 2018 के बाद यह उनकी पहली चीन यात्रा होगी। मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आखिरी मुलाकात अक्टूबर 2024 में रूस में हुई थी। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स का अनुमान है कि संचयी टैरिफ जो न केवल भारत के वियतनाम जैसे निर्यात प्रतिद्वंद्वियों, बल्कि चीन के टैरिफ से भी ज्यादा हैं अमेरिका को होने वाले निर्यात में 60% की कमी ला सकते हैं और जीडीपी में लगभग एक प्रतिशत की कमी ला सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026 में अर्थव्यवस्था 6.5% बढ़ेगी-जो पिछले साल के बराबर है और उससे पहले देखी गई औसत 8% वृद्धि से काफी कम है।

50 साल पुरानी डाक सुविधा अब बनेगी इतिहास, 1 सितंबर से नहीं कर पाएंगे रजिस्टर्ड पोस्ट

(एजेन्सी)। **भारतीय** डाक विभाग 1 सितंबर, 2025 से अपनी पंजीकृत डाक सेवा बंद करने की योजना बना रहा है। यह निर्णय 50 वर्षों से भी अधिक समय से चली आ रही एक सेवा के अंत का प्रतीक है और डाक संचालन को आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए स्पीड पोस्ट के साथ रणनीतिक एकीकरण का एक हिस्सा है। विभाग पंजीकृत डाक सेवा को स्पीड पोस्ट के साथ विलय करने की योजना बना रहा है। पंजीकृत डाक की कीमत 25.96 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए 5 रुपये अतिरिक्त थी, जबकि स्पीड पोस्ट की शुरूआती कीमत 50 ग्राम तक के पार्सल के लिए 41 रुपये है, जिससे यह 20-25 प्रतिशत महंगा हो जाता है।

बढ़ी हुई लागत छोटे व्यापारियों, किसानों और दूरदराज के इलाकों के नागरिकों को प्रभावित कर सकती है जो सस्ती डाक सेवाओं पर निर्भर हैं। डाक सचिव और महानिदेशक ने सभी विभागों, न्यायालयों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य उपयोगकताओं को 1 सितंबर तक यह परिवर्तन पूरा करने का निर्देश दिया है। इस विलय का उद्देश्य 1986 से उपयोग में आ रही स्पीड पोस्ट प्रणाली के तहत बेहतर ट्रैकिंग, तेज डिलीवरी समय और बेहतर परिचालन दक्षता के माध्यम से सेवा वितरण को बेहतर बनाना है। यह कदम पंजीकृत डाक की मांग में लगातार गिरावट के बाद उठाया गया है, जिसका कारण डिजिटल माध्यमों का बढ़ता उपयोग और निजी कूरियर सेवाओं व ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स से प्रतिस्पर्धा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पंजीकृत वस्तुओं की संख्या में 25 प्रतिशत की गिरावट आई है—2011-12 में 24.44 करोड़ से घटकर 2019-20 में 18.46 करोड़ रह गई। हालाँकि स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग और डिलीवरी की पावती जैसी प्रमुख सुविधाएँ प्रदान करता रहेगा, लेकिन इस निर्णय ने उपयोगकताओं, विशेष रूप से पुरानी पीढ़ियों और ग्रामीण समुदायों में पुरानी यादें ताजा कर दी हैं। पंजीकृत डाक को लंबे समय से विश्वास का प्रतीक माना जाता रहा है, जो अपनी कानूनी वैधता, सामर्थ्य और विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है।

ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान शुरू हुई पंजीकृत डाक ने सुरक्षित और कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त दस्तावेज वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बैंकों, विश्वविद्यालयों, न्यायालयों और सरकारी विभागों द्वारा इसके साक्ष्य मूल्य के कारण इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था, और डाक और वितरण का प्रमाण अक्सर कानूनी कार्यवाहियों में स्वीकार्य होता था। इसका बंद होना भारत के संचार ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है।

रक्षा-पर्यावरण मंत्री समेत 8 की मौत, हादसे की वजह साफ नहीं

(एजेन्सी)। **घाना** एक सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दो प्रमुख कैबिनेट मंत्रियों सहित आठ लोगों की मौत के बाद शोक में डूब गया। सरकार ने रक्षा मंत्री एडवर्ड ओमान बोआमाह और पर्यावरण मंत्री इब्राहिम मुर्तला मुहम्मद की मृत्यु की पुष्टि करते हुए इस घटना को राष्ट्रीय त्रासदी बताया। घाना सशस्त्र बलों के अनुसार, `-9 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ने सुबह राजधानी अकरा से उड़ान भरी थी और यह अशांति क्षेत्र के एक प्रमुख स्वर्ण खनन केंद्र ओबुआसी के लिए रवाना हुआ था। हालाँकि, उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद, विमान रडार से गायब हो गया। दुर्घटना का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। दोनों मंत्रियों के अलावा, पीड़ितों में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक कांग्रेस के उपाध्यक्ष, एक वरिष्ठ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चालक दल के सदस्य भी शामिल थे। आमतौर पर परिवहन और चिकित्सा निकासी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला `-9 हेलीकॉप्टर कथित तौर पर एक आधिकारिक मिशन पर था जब यह दुर्घटनाग्रस्त हुआ।

इस त्रासदी के बाद, राष्ट्रपति जॉन महामा ने सभी आधिकारिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है और सम्मान स्वरूप पूरे देश में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रखने का निर्देश दिया है। चीफ ऑफ स्टाफ जूलियस डेब्राह ने इस घटना को "राष्ट्रीय त्रासदी" बताया और देश की सेवा में अपनी जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की। रिपोर्टों के अनुसार, मंत्रियों की अचानक मृत्यु ने सुरक्षा और पर्यावरण नीति में महत्वपूर्ण खामियाँ पैदा कर दी हैं। डॉक्टर से राजनेता बने रक्षा मंत्री एडवर्ड ओमान बोआमाह ने हाल ही में बुर्किना फासो में सीमा पार सक्रिय इस्लामी आतंकवादियों से बढ़ते खतरों के बीच घाना की सीमा सुरक्षा को मजबूत किया था। इससे ठीक तीन महीने पहले, उन्होंने उत्तरी घाना में हथियारों के प्रवाह को रोकने के लिए बुर्किना फासो के सैन्य नेताओं के साथ उच्च-स्तरीय कूटनीतिक वार्ता का नेतृत्व किया था।

पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज को चुभी टीम इंडिया की जीत

(एजेन्सी)। **पाकिस्तान** के पूर्व तेज गेंदबाज शब्बीर अहमद ने इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में खेले गए एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के पांचवें और अंतिम टेस्ट मैच में भारत पर गेंद से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। अहमद ने आईसीसी अंपायरों से आग्रह किया कि वे श्रृंखला के अंतिम मैच के चौथे और पाँचवें दिन भारत द्वारा इस्तेमाल की गई गेंद को 'लैब जाँच' के लिए भेजें। अहमद की यह प्रतिक्रिया भारत द्वारा छह रनों से अपनी सबसे करीबी जीत दर्ज करने और पाँच मैचों की श्रृंखला 2-2 से बराबर करने के बाद आई है।

भारत बनाम इंग्लैंड पाँचवें टेस्ट के पाँचवें दिन मोहम्मद सिराज ने लगभग 80 ओवर पुरानी गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराया। प्रसिद्ध कृष्णा ने भी ऐसा ही किया। शायद सिराज जितना नहीं, लेकिन उन्होंने भी गेंद को तेजी से घुमाया। इतना कि भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने दूसरी नई गेंद लेने के बारे में सोचा भी नहीं, तब भी जब भारत को इंग्लैंड के आखिरी तीन विकेटों की जरूरत थी और 30 रन से भी कम का खेल बचा था। और इसका भरपूर फायदा हुआ। हालाँकि, पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शब्बीर अहमद भारतीय तेज गेंदबाजों के कौशल की सराहना करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने इसके बजाय, उन पर गेंद की चमक बनाए रखने के लिए 'वैसलीन' का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, भले ही वह पुरानी हो गई हो। पाकिस्तान के लिए 10 टेस्ट और 3 वनडे खेलने वाले इस पूर्व दुबले-पतले दाएँ हाथ के मध्यम गति के गेंदबाज ने पिच, बादलों से घिरी परिस्थितियों और सबसे बढ़कर, सिराज और कृष्णा की कला को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने पर लिखा मुझे लगता है कि भारत ने वैसलीन का इस्तेमाल किया। 80+ ओवर के बाद भी गेंद नई जैसी चमक रही है। अंपायर को इस गेंद को जाँच के लिए लैब में भेजना चाहिए।

यह पहली बार नहीं था जब किसी पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने भारत पर गेंद की स्थिति से छेड़छाड़ का आरोप लगाया हो। 2023 के वनडे विश्व कप के दौरान, जब मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और सिराज ने टूर्नामेंट में किसी भी अन्य नए गेंदबाज की तुलना में नई गेंद को कहीं ज्यादा स्विंग कराया था, तब पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन रजा ने कहा था कि आईसीसी भारत को एक "अलग गेंद" दे रहा है।

श्वेता मेनन के खिलाफ एफआईआर की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाई

(एजेन्सी)। एनार्कुलम सेंट्रल पुलिस ने मशहूर मलयालम अदाकारा श्वेता मेनन के खिलाफ एक शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने पैसे कमाने के इरादे से अश्लील और अश्लील सामग्री वाली फिल्मों और विज्ञापनों में काम किया। अदालत के निर्देशानुसार, अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम 1956 की धारा 5, 3 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67(ए) के तहत मामला दर्ज किया गया था। अब केरल उच्च न्यायालय ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है। केरल उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को मलयालम फिल्म अभिनेत्री श्वेता मेनन के खिलाफ दर्ज उस प्राथमिकी के संबंध में कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें मेनन पर उनकी कुछ पिछली फिल्मों और विज्ञापनों के अश्लील दृश्यों को कथित तौर पर प्रकाशित या प्रसारित करने का आरोप है। न्यायमूर्ति वी जी अरुण ने अभिनेत्री द्वारा अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए दायर याचिका पर यह आदेश दिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि अभिनेत्री के वकील की इस दलील में प्रथम दृष्टया दम है कि शिकायत को जांच के लिए भेजने से पहले पुलिस से रिपोर्ट मांगने और जांच करने की आवश्यकताओं का पालन किया जाना चाहिए था।

अद्भूत गर्व, एकता और देशभक्ति की भावना को जगाता है तिरंगा: डीसी प्रीति

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

कैथल। डीसी प्रीति ने कहा कि तिरंगा केवल एक झंडा नहीं, बल्कि हमारे संविधान, स्वतंत्रता और संप्रभुता का प्रतीक है। तिरंगा हमारे भीतर एक अद्भूत गर्व, एकता और देशभक्ति की भावना को जागृत करता है। सभी नागरिक तिरंगे का सम्मान करें और इसकी गरिमा बनाए रखें। सरकार तथा प्रशासन द्वारा जिला में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर विभिन्न कार्यक्रम जिला स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। सभी नागरिक इसमें बढ़चढ़ कर भाग लें।

डीसी प्रीति वीरवार को लघु सचिवालय में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत रेडक्रॉस सोसायटी के वॉलिंटियर्स द्वारा तिरंगा जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाने उपरांत बोल रहीं थीं। यह तिरंगा जागरूकता रैली लघु सचिवालय से नए बस स्टैंड होते हुए रेडक्रॉस कार्यालय में संपन्न हुई। तिरंगा रैली के दौरान हाथों में तिरंगा लिए हुए प्रतिभागियों ने देशभक्ति के नारे लगाए। डीसी प्रीति ने कहा कि तिरंगा भारत का गौरव, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि उन असंख्य बलिदानों की, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि तिरंगे में तीन रंग होते हैं, जिसमें केसरियां रंग जो बलिदान, साहस और त्याग का प्रतीक है। सफेद रंग जो शांति, सच्चाई और ईमानदारी को दर्शाता है। हरा रंग जो समृद्धि, हरियाली और विकास का प्रतीक है। बीच में बना नीले रंग का अशोक चक्र जो न्याय, गति और धर्म का प्रतीक है। यह झंडा हमें याद दिलाता है कि हम एक राष्ट्र, एक संस्कृति और एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमें तिरंगे का अपने घर पर लहराने के साथ-साथ इसके सिद्धांत जैसे सच्चाई, भाईचारा, समर्पण और सेवा भाव को अपने जीवन में उतारना चाहिए।

एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। इस मौके पर जिला रैडक्रॉस सचिव रामजी लाल, डॉ. बीरबल दलाल आदि मौजूद रहे।

जेजे कॉलोनियों का विकास और झुग्गियों का पुनर्वास सरकार की प्राथमिकता: रविन्द्र इंद्राज

दिल्ली को कूड़े से आजादी-स्वच्छता अभियान में जनसहभागिता का आह्वान

संजना भारती संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने गुरुवार को बवाना विधानसभा के शाहबाद दौलतपुर डेयरी स्थित न्यू ए ब्लॉक में नालियों और सड़कों के पूर्ण हुए निर्माण कार्यों को स्थानीय नागरिकों को समर्पित किया।

कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री ने क्षेत्रीय निवासियों से संवाद के दौरान कहा कि सरकार का प्रयास है कि दिल्ली की सभी कॉलोनियों, विशेष रूप से विकास में पिछड़े और अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराया जाए।

समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के गरीब कल्याण संकल्प की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जे जे कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं के विकास और झुग्गियों के पुनर्वास को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इन योजनाओं पर दिल्ली में पहली बार व्यापक प्रयास हो रहे हैं।

श्री इंद्राज ने कहा कि स्वच्छता, स्वास्थ्य और सम्मान हर नागरिक का अधिकार है। दिल्ली सरकार इसी सोच के साथ हर बस्ती में पक्की सड़कों, नालियों और साफ गलियों का निर्माण कर रही है। शाहबाद डेयरी क्षेत्र में लगातार हो रहे विकास कार्य इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। समाज कल्याण मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां भी आवश्यकता है, वहां बचे हुए निर्माण कार्यों की जल्द रूपरेखा तैयार की जाए और चल रहे कार्यों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण करें।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अगस्त माह में आजादी के पर्व को लेकर राज्य सरकार ने दिल्ली को कूड़े से आजादी-स्वच्छता अभियान की शुरूआत की है। यह केवल सरकारी प्रयास नहीं, बल्कि जनआंदोलन है। उन्होंने लोगों से श्रमदान करने और अपने मोहल्लों, कॉलोनियों, पार्कों को साफ-सुथरा रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता एक आदत नहीं, एक संस्कार है। महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम स्वच्छ, सुंदर और विकसित भारत के निर्माण में योगदान दें। श्री इंद्राज ने कहा कि दिल्ली सरकार का स्वच्छता पोर्टल अब प्रत्येक नागरिक कल्याण समिति के लिए भी खुला है। समितियां स्वच्छता से जुड़े कार्यों, जैसे-सफाई अभियान, श्रमदान, जागरूकता रैली आदि के फोटो और विवरण पोर्टल पर अपलोड करें, जिससे उनके कार्यों को पहचान व प्रोत्साहन मिल सके।

स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चों ने झोंकी ताकत

संजना भारती संवाददाता

कैथल। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का चयन जाखौली अड्डा स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के हॉल में एडीसी दीपक बाबू लाल करवा की अगुवाई में गठित कमेटी द्वारा किया गया। इस मौके पर विभिन्न स्कूल के बच्चों ने जहां देश भक्ति से ओत-प्रोत प्रस्तुतियां दी, वहीं विभिन्न संस्कृतियों की झलक भी देखने को मिली। विद्यार्थियों ने पूरे जोश के साथ प्रस्तुतियां दी और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

समारोह के लिए विभिन्न स्कूल के बच्चों द्वारा तैयारियां की जा रही थी। सभी बच्चों ने अच्छी प्रस्तुतियां दी, उनमें से बेहतरीन प्रस्तुतियों का चयन किया गया। जिनमें जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चों का समूह गान, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जाखौली अड्डा के छात्राओं का हरियाणवी नृत्य, राधा कृष्ण पब्लिक स्कूल की पहलगाम एवं ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित कोरियोग्राफी, सिल्वर ऑक स्कूल के विद्यार्थियों का विभिन्न संस्कृतियों पर आधारित कोरियाग्राफी, आरकेएसडी पब्लिक स्कूल के बच्चों ने देश के विभिन्न संस्कृतियों पर आधारित प्रस्तुति, नर नारायण सेवा समिति के बच्चों ने चकदे हरियाणा गीत पर देशभक्ति प्रस्तुति सहित सुपार्श्व जैन स्कूल की टीम की सेना व पुलिस को लेकर कोरियोग्राफी शामिल हैं। इसके अलावा राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जाखौली अड्डा के बच्चों द्वारा राष्ट्रगान की प्रस्तुति का चयन किया गया। चयन कमेटी के अध्यक्ष एडीसी दीपक बाबूलाल करवा ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के चयन के समय सभी स्कूलों के ईंचार्ज को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और समारोह की गरिमा के अनुरूप कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए कहा। जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कमियां नजर आई, उन्हें दूर करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने विद्यार्थियों को निरंतर अभ्यास जारी रखने और प्रस्तुतियों में ओर अधिक निखार लाने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अंतिम पूर्वाभ्यास 13 अगस्त को पुलिस लाइन मैदान में होगा। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में देशभक्ति सहित सामाजिक मूल्यों पर अच्छा संदेश देने का प्रयास किया जाए।

इस मौके पर एडीसी दीपक बाबूलाल करवा, जिला शिक्षा अधिकारी डा. विजय लक्ष्मी, डीआईपीआरओ नसीब सैनी, एआईपीआरओ अमित कौशिक, प्रवीण थरेजा आदि मौजूद रहे।

राजौंद में पीडब्ल्यूडी द्वारा कंडम घोषित सरकारी अस्पताल की इमारत बनी खतरे की घंटी, खुंखार बंदरों ने कंडम इमारत को बनाया आशियाना

स्थानीय नागरिकों ने मुख्यमंत्री से कंडम इमारत को गिरवाने की मांग की

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

राजौंद। राजौंद के कैथल मार्ग पर स्थित नगर के सरकारी अस्पताल की पुरानी इमारत, क्वार्टर, पुराना कार्यालय खतरे का केंद्र बन चुकी है। यह इमारत वर्षों पहले ही लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) कैथल द्वारा कंडम घोषित कर दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद अब तक इसे गिराया नहीं गया है। मौजूदा समय में यह जर्जर भवन पूरी तरह से जमीनी सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर खड़ा है, जो किसी भी समय गिरकर बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है।

स्थानीय लोगों सुरेश कुमार, पवन, नवाब, तरसेम सहित अन्य ने बताया कि इस इमारत में उत्पाती बंदरों ने अपना अड्डा बना लिया है। बंदरों की गतिविधियों से आसपास आने-जाने वाले मरीजों, स्टाफ व राहगीरों को रोजाना खतरा बना रहता है। कई बार खूंखार बंदर अस्पताल स्टाफ व मरीजों को काट कर घायल कर चुके हैं। बरसात के मौसम में यह खतरा और अधिक बढ़ गया है क्योंकि कमजोर दीवारें और छत कभी भी ढह सकती हैं।

नागरिकों का कहना है कि पीडब्ल्यूडी प्रशासन कैथल की अनदेखी से यह इमारत अब जानलेवा बनती जा रही है। यदि समय रहते इसे नहीं गिराया गया, तो यह कोई बड़ी अनहोनी का कारण बन सकती है। इसके चलते राजौंद के जागरूक नागरिकों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से गुहार लगाई है कि वह पीडब्ल्यूडी विभाग, कैथल को इस इमारत को जल्द गिराने के निर्देश देवें।

सरकारी हस्पताल राजौंद की कंडम इमारत। (छाया: एसबी)

स्थानीय प्रशासन से भी मांग की गई है कि कंडम इमारत के चारों ओर वाहन खड़े न हो और आमजन की आवाजाही पर रोक लगाई जाए, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। नागरिकों का कहना है कि जनहित में त्वरित कार्रवाई समय की मांग है।

इस मामले के बारे में पीडब्ल्यूडी विभाग कैथल के एसडीओ सुरेंद्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कंडम इमारत को डिमोलिश करवाने के दो तरीके होते हैं पहले नंबर पर विभाग कंडम इमारत को तुड़वाकर मलवा इकट्ठा करके बोली लगाकर उसे सेल करता है। दूसरा तरीका जब नई इमारत बनाई जानी हो तो विभाग पुरानी इमारत की कीमत लगाकर उसे साफ करवाता है व नई इमारत वहां पर बनता है। उन्होंने कहा कि सीएससी राजौंद को आगामी कार्रवाई करनी है।

सीएचसी राजौद के एसएमओ डॉक्टर कीर्ति कुमार शर्मा व चिकित्सा अधिकारी संदीप सिंह से फोन पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि लगभग तीन साल पहले पीडब्ल्यूडी विभाग कैथल ने इस इमारत को कंडम घोषित किया था। इसे डिमोलिश करने के लिए लगभग एक साल से पीडब्ल्यूडी विभाग कैथल से पत्र व्यवहार चल रहा है। लेकिन अभी तक विभाग ने इसे डिमोलिश नहीं किया है। उम्मीद है कि पीडब्ल्यूडी विभाग कैथल बहुत जल्द इसे डिमोलिश करेगा।

इमारत पर खुंखार बंदरों का कब्जा। (छाया: एसबी)

सरकारी हस्पताल राजौंद की कंडम इमारत। (छाया: एसबी)

वरिष्ठ नागरिक महिला डॉक्टर के साथ हुई सनसनीखेज डकैती का मामला सुलझा

इंस्पेक्टर हरि सिंह.

संजना भारती संवाददाता
मनोज प्रजापति

नई दिल्ली। घटनास्थल/घटनास्थल से 700 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में लगे 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की जाँच के बाद दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में लगे सीसीटीवी कैमरों की जाँच के बाद आरोपी की पहचान हुई।

छह सोने की चेन, एक सोने का चेन का हुक, एक चोरी की अपाचे बाइक, एक बजाज अपराध करने में इस्तेमाल की गई डोमिनार 400 बाइक और अपराध के समय पहने गए कपड़े बरामद। लूट, झपटमारी और वाहन चोरी के कुल 7 मामलों का खुलासा हुआ। दो शातिर और आदतन अपराधियों आरोपी दानिश उर्फ चिंटू थाना पुल प्रह्लादपुर का बीसी है और पहले हत्या, लूट, झपटमारी आदि के 40 से ज्यादा मामलों में शामिल रहा है। वह गैंगस्टर भी है और चिंटू गैंग के नाम से गिरोह चलाता है। डॉ. एसए के बयान पर, एफआईआर संख्या 285/25, धारा 309(6)/3(5) बीएनएस के तहत, पुलिस स्टेशन सफदरजंग एन्क्लेव, दिल्ली में एक डकैती का मामला दर्ज किया गया था। इसमें उन्होंने बताया था कि 25/07/25 को दोपहर लगभग 03:00 बजे, जब वह ग्रीन फील्ड स्कूल, सफदरजंग, दिल्ली के पास अपनी कार के किनारे खड़ी थीं, तभी दो व्यक्ति बाइक पर आए और ग्रीन फील्ड स्कूल, सफदरजंग, दिल्ली के पास उन्हें धक्का देकर उनकी सोने की चेन लूट ली और भाग गए। सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर पता चला कि दोनों घटनाओं में अपराधी एक ही हैं।

मामले को सुलझाने के लिए, इंस्पेक्टर हरि सिंह, प्रभारी एंटी-स्नैचिंग सेल/दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र के नेतृत्व में और श्री विजय सिंह, सहायक पुलिस आयुक्त/संचालन/दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र के पर्यवेक्षण में अपराधियों को पकड़ने के लिए एसआई कमल कांत, एसआई पंकज लांबा, हेड कांस्टेबल अनिल, हेड कांस्टेबल नरेंद्र, हेड कांस्टेबल शीशराम, हेड कांस्टेबल दिलीप, हेड कांस्टेबल राजकुमार, हेड कांस्टेबल मुकेश, हेड कांस्टेबल संदीप, हेड कांस्टेबल सांवता राम, कांस्टेबल संदीप, कांस्टेबल सनी और कांस्टेबल बबलू की एक समर्पित टीम गठित की गई। टीम ने स्थानीय खुफिया जानकारी जुटाई और गिरफ्तार कर लिया आगे की जाँच जारी है।

राजौंद में जल्द बनेगा सरकारी कॉलेज: काका राणा

'कॉलेज बनाओ-सिवरेज हटाओं' संघर्ष समिति की मेहनत लाई रंग

■ संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी, सांसद कुरुक्षेत्र नवीन जिंदल का किया धन्यवाद

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

राजौंद। राजौंद वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लंबे समय से सरकारी कॉलेज भवन की मांग कर रहे लोगों को अब राहत मिलने वाली है। ह्याकॉलेज बनाओ - सिवरेज हटाओह्व संघर्ष समिति के प्रवक्ता सतविंद्र राणा उर्फ काका राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें कुरुक्षेत्र सांसद नवीन जिंदल कार्यालय से संदेश प्राप्त हुआ है कि 15 अगस्त तक राजौंद में सरकारी कॉलेज के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसका टेंडर खुल चुका है।

काका राणा ने बताया कि प्रस्तावित कॉलेज का निर्माण राजौंद के सरकारी बस अड्डे के सामने स्थित पीडब्ल्यूडी परिसर में किया जाएगा। यह वही स्थान है, जिसे लेकर काफी समय से संघर्ष चल रहा था। क्षेत्र के छात्र -छात्राएं व अभिभावक काफी समय से यह मांग कर रहे थे कि राजौंद में सरकारी कॉलेज, सरकारी बस अड्डे के सामने पीडब्ल्यूडी परिसर में बने, ताकि विद्यार्थियों को आने जाने में सुविधा हो। संघर्ष समिति के अनुसार, राजौंद जैसे तेजी से विकसित हो रहे नगर में कॉलेज भवन की अनुपस्थिति एक बड़ी शैक्षणिक कमी थी। इस मांग को पूरा करने के लिए कई बार ज्ञापन, प्रदर्शन और जन समर्थन के माध्यम से यह मांग सरकार व शासन तक पहुंचाई गई थी। अब, जब सांसद कार्यालय की ओर से यह सकारात्मक संदेश मिला है, तो क्षेत्र में उत्साह की लहर है। काका राणा ने मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी और सांसद नवीन जिंदल का आभार जताते हुए कहा कि यह निर्णय राजौंद क्षेत्र के युवाओं के भविष्य को नई दिशा देगा। उन्होंने आशा जताई कि कॉलेज निर्माण कार्य समय पर शुरू होकर शीघ्र ही पूरा भी होगा।

मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी।

पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल।

गौरतलब है कि राजौद में सरकारी कॉलेज की मांग कलायत की पूर्व विधायक एवं तत्कालीन राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा ने तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को राखी बांधते हुए बदले में राजौंद के लिए सरकारी कॉलेज की मांग की थी। जिसे उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सहर्ष स्वीकार कर लिया था। राजौद में सरकारी कॉलेज बनाने में पूर्व राज्य मंत्री कमलेश ढांडा का भी अहम सहयोग रहा है। उनकी मांग पर ही राजौद में सरकारी कॉलेज आया है। पूर्व राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के प्रयास को बुलाया नहीं जा सकता।

सांसद कुरूक्षेत्र नवीन जिंदल।

संघर्ष समिति प्रधान राकेश राणा व सभी पदाधिकारियों, सदस्यों ने बताया कि सरकारी बस अड्डे के सामने पीडब्ल्यूडी परिसर में सरकारी कॉलेज बनने से विद्यार्थी गर्मी, सर्दी, बारिश किसी भी मौसम में आसानी से बस अड्डे से बस लेकर आना-जाना कर सकेंगे।न केवल राजौंद नगर बल्कि आसपास के क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए भी यह जगह बेहतर साबित होगी।

बताया गया कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी जब कैथल आए थे तो उन्होंने घोषणा की थी कि राजौंद नगर में 5 एकड़ भूमि में बहुमत जिला सरकारी कॉलेज इमारत बनाई जाएगी। जिसे सरकार बहुत जल्द पूरा करने वाली है। इससे सूचना से नगर व क्षेत्र में खुशी की लहर है।

पूर्व विधायक कलायत एवं तात्कालिक राज्य मंत्री कमलेश ढांडा।

मुख्यमंत्री और संत निरंजन दास जी ने डेरा सचखंड बल्लां में एस.टी.पी. का किया शिलान्यास

संजना भारती/विज्ञप्ति द्वारा

बल्लां (जालंधर)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने डेरा सचखंड बल्लां में लगभग 3.4 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी.) और मुख्य पंपिंग स्टेशन का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर डेरा सचखंड बल्लां में नतमस्तक होकर डेरा प्रमुख संत निरंजन दास जी से आशीर्वाद प्राप्त किया।

श्रद्धा प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महान धार्मिक नेताओं के चरण स्पर्श और इस पावन स्थल के दर्शन का अवसर पाकर वे स्वयं को धन्य महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह धरती सदैव विश्व शांति, भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द की मूल्यों को प्रोत्साहित करती रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा दिखाए मार्ग पर चलते हुए पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य प्रमुख क्षेत्रों के साथ-साथ शिक्षा को भी प्राथमिकता दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार पहले ही इन क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण पहल कर चुकी है। उन्होंने बताया कि पंजाब ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के एक नए युग की शुरुआत की है और आज शैक्षणिक परिणामों में पंजाब देश का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने गर्व से कहा कि अब कमजोर और पिछड़े वर्गों के विद्यार्थी भी नीट और जेईई जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, जो राज्य सरकार के समर्पित प्रयासों का परिणाम है।

राज्य सरकार की एक और ऐतिहासिक पहल का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने 'मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना' का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि देशभर में अपनी तरह की इस पहली योजना के अंतर्गत पंजाब के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मुहैया कराया जा रहा है।

शिक्षा के साथ-साथ संस्कारों का विद्यार्थी जीवन में बड़ा महत्व: विधायक योगेन्द्र राणा

एसबी ब्यूरो प्रमुख/विजय गर्ग

असंध। असंध के गांव पाढा स्थित आर्य कन्या गुरूकुल में आयोजित स्वागत समारोह में गुरुवार को विधायक योगेन्द्र राणा ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। गुरुकुल प्रांगण में पहुंचने पर गुरुकुल प्रशासन व ग्रामवासियों द्वारा विधायक का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान विधायक योगेन्द्र राणा ने कहा कि आज के समय में शिक्षा से बड़ा कोई कार्य नहीं है। शिक्षा के साथ साथ संस्कारों का विद्यार्थी जीवन में बड़ा महत्व है, ऐसे में शिक्षक विद्यार्थियों को बेहतरीन शिक्षा प्रदान करते हुए चरित्र निर्माण पर बल दें।

विधायक गुरूवार को गांव पाढा स्थित आर्य कन्या गुरूकुल में आयोजित स्वागत समारोह में बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे। विधायक ने इस मौके पर विद्यालय में विकास कार्यों के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। उन्होंने विद्यार्थियों को दूर दृष्टि, कडी मेहनत व पक्का इरादा और गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने गुरुकुल की उन्नति के लिए हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। विधायक का सर्वप्रथम आर्य कन्या गुरूकुल में पहुंचने पर प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों व ग्रामीणों ने पुष्पगुच्छ देकर व फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आर्य कन्या गुरूकुल अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण गुरूकुल है। इस प्रकार की संस्थाएं सबके सहयोग से चलती है और निश्चित रूप से प्रदेश सरकार भी सभी संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए अग्रसर है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी आभार जताया। गुरुकुल की प्रबंधन समिति ने मुख्य अतिथि का गुरुकुल प्रांगण मे पधारने व विद्यार्थियों को अपना आशीर्वाद देने पर धन्यवाद दिया।

इस अवसर पर गुरुकुल प्रधान सुभाष साध पाढा, उप प्रधान महेन्द्र, नसीब सिंह कुरलन, डॉ. महासिंह, जसबीर सिंह, जय भगवान अत्री, कोषाध्यक्ष धर्मवीर सिंह पाढा, चेयरमैन-वेद प्रकाश ढुल पाढा, वाईस चेयरमैन-बलजीत सिंह पाढा, प्रबंधक-कर्मवीर सिंह पाढा, सह प्रबंधक-जोगिंदर सिंह पाढा, बल्ला मंडल अध्यक्ष जय भगवान जांगड़ा, अमित राणा, सुरेंद्र कश्यप, महिला मोर्चा पूर्व मंडल अध्यक्ष नीलम सहित अन्य ग्रामवासी मौजूद रहे।

सरपंच राजनीति से ऊपर उठकर करें काम: हरविन्द्र कल्याण

स्वच्छता, पौधारोपण और योजनाओं के लाभ पर दें ध्यान

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी

करनाल। विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने गुरुवार को करनाल लघु सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में घरौंडा विधानसभा क्षेत्र के सरपंचों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि सरपंच राजनीति से ऊपर उठकर गांवों में विकास की योजनाएं बनाएं और प्राथमिकताओं के अनुसार काम करें। उन्होंने सरपंचों से आह्वान किया कि स्वच्छता, पौधारोपण और गरीबों के लिए बनी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने पर विशेष ध्यान दें। स्वच्छता से गांवों का स्तर बढ़ता है। तालाबों से गंदे पानी की निकासी कराएं और पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिकाधिक पौधे लगाएं। इसके लिए पंचायती या सरकारी जमीन का उपयोग किया जा सकता है।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। इसलिए पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी सभी की है। उन्होंने सरपंचों से अपील की कि वे सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान दें। मनरेगा जैसी योजनाओं से गांवों में कई कार्य करवाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर की भावना से कार्य करें और यह सुनिश्चित करें कि लाभ केवल पात्र लोगों को ही मिले।

हरविन्द्र कल्याण ने बताया कि 2014 के बाद से घरौंडा क्षेत्र में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटी, एनसीसी अकादमी और रिंग रोड जैसे प्रोजेक्ट क्षेत्र में आ चुके हैं। कई स्कूलों और अस्पतालों को क्रमोन्नत किया गया है। करनाल में नई चीनी मिल स्थापित की गई है। गांवों में ग्रांट के माध्यम से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं और लंबित योजनाओं को प्राथमिकता से पूरा किया जा रहा है।

बैठक में उपायुक्त उत्तम सिंह, एसडीएम अनुभव मेहता, डीडीपीओ संजय टांक सहित विभिन्न गांवों के सरपंच और प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

सीतामाई में आयोजित जिला स्तरीय वन महोत्सव में विधानसभा अध्यक्ष ने की लोगों से अपील

हर व्यक्ति लगाएं पौधे, तभी बचेगा पर्यावरण: हरविन्द्र कल्याण

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी

करनाल। विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। यदि हर व्यक्ति एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे, तो आने वाली पीढ़ियों को हम शुद्ध व सुरक्षित वातावरण दे सकते हैं। वे गुरुवार को सीतामाई में आयोजित जिला स्तरीय वन महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे।

कल्याण ने कहा कि पेड़ जीवनदायिनी ऑक्सीजन मुफ्त में देते हैं। कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए लोगों ने कितनी मशक्कत की, यह हम सभी जानते हैं। उस समय हमें प्रकृति की अहमियत का एहसास हुआ। उन्होंने कहा कि सिर्फ पौधे लगाना ही नहीं, बल्कि उनकी देखभाल करना भी जरूरी है। पेड़ों को बच्चों की तरह पालना होगा। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर में माथा टेकने के बाद पंचायत भूमि पर पौधारोपण किया। स्कूली विद्यार्थियों ने करीब एक हजार पौधे लगाए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि पर्यावरण संतुलन के लिए जनभागीदारी जरूरी है। सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन आमजन का सहयोग मिले बिना लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने बच्चों को भी इस मुहिम से जोड़ने की जरूरत बताई। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मोहड़ी व रिद्म वैली स्कूल, मोहड़ी के विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपये की सम्मान राशि देने की घोषणा की। कार्यक्रम में नीलोखेड़ी के विधायक भगवानदास कबीरपंथी ने कहा कि यह वन महोत्सव किसी पर्व से कम नहीं है। सावन में चल रहे "एक पेड़ मां के नाम" अभियान के तहत हजारों पौधे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि हम अच्छा जीवन चाहते हैं, तो पर्यावरण की रक्षा करनी होगी।

असंध से विधायक योगेंद्र राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीर है। "प्राण वायु देवता" योजना के तहत 75 वर्ष से अधिक पुराने पेड़ों को पेंशन दी जा रही है। वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिला परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि सोहन सिंह राणा ने कहा कि पौधे जलवायु परिवर्तन से लड़ने, मिट्टी के कटाव को रोकने और जैव विविधता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए पौधों की देखभाल पेड़ बनने तक जरूरी है। जिला वन अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि वन विभाग की ओर से हर वर्ष स्कूली बच्चों को 50 हजार पौधे वितरित किए जाते हैं। वन मित्रों को प्रति पौधा 120 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

कार्यक्रम में उपायुक्त उत्तम सिंह, एसडीएम अशोक कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रवीन लाठर, चेयरपर्सन निर्मला बैरागी, डीईओ सुदेश ठुकराल, बीडीपीओ आशुतोष, भाजपा नेत्री मीना चौहान, मंदिर सेवा समिति के पदाधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि और स्कूली बच्चे उपस्थित रहे।

राजौंद में खंड स्तरीय स्कूल लेवल प्रतियोगिता का हुआ समापन

खंड शिक्षा अधिकारी बलबीर सिंह कश्यप ने विजेता खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

राजौंद। राजौंद में खंड स्तरीय स्कूल लेवल प्रतियोगिता का शानदार समापन हुआ। खेल नोडल अधिकारी सोहन पाल ने बताया आज के परिणाम निम्न अनुसार रहे। कबड्डी अंडर 14 लड़कियां प्रथम स्थान गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सौंगरी गुलियाना, द्वितीय स्थान गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कसान ने प्राप्त किया। अंडर 17 लड़कियां प्रथम स्थान गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सौंगरी गुलियाना ने प्राप्त किया। द्वितीय स्थान गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कसान ने प्राप्त किया। अंडर-19 में प्रथम स्थान गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कसान ने प्राप्त किया। द्वितीय स्थान गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सौंगरी गुलियाना ने प्राप्त किया। इसी तरह से फुटबॉल में अंडर-19 लड़कियां प्रथम स्थान गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजौंद ने प्राप्त किया। खो- खो अंडर-19 लड़कियां गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजौंद ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अंडर 17 लड़कियां प्रथम स्थान गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल जाखौली ने प्राप्त किया। इस अवसर पर वीरेंद्र देओल प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहड़ा, नरेंद्र कुमार प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल जाखोली, कुलदीप पूर्व हसला प्रधान राजौंद, राजेंद्र पी जी टी रोहड़ा, अमित आर्य, राजौंद खंड के सभी पीटीआई एवं डीपीई तथा अन्य गण मान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इन खेलों का आयोजन खंड शिक्षा अधिकारी बलवीर सिंह कश्यप की देख रेख में संपन्न हुआ। बलवीर सिंह कश्यप ने खेलो के समापन के अवसर पर विजेता खिलाडियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने इन खेलों का सफल आयोजन करने के लिए नोडल अधिकारी, स्कूल प्रिंसिपल, डीजी, पीटीआई, सहयोगी स्टाफ, ग्राम सरपंच, अभिभावको का धन्यवाद किया।

श्रद्धानंद बाल संरक्षण संस्थान में बाल अधिकार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

बच्चों को बताया गया अधिकारों और सुरक्षा कानूनों के बारे में

एसबी विशेष संवाददाता

करनाल। श्रद्धानंद बाल संरक्षण संस्थान में वीरवार को बाल अधिकारों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य संस्थान में रह रहे बच्चों को उनके मूलभूत अधिकारों, सुरक्षा से जुड़े कानूनों और सहायता तंत्र की जानकारी देना था।

कार्यक्रम में जिला बाल संरक्षण अधिकारी रीना रानी ने बच्चों को बताया कि संविधान और कानून हर बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, चिकित्सा और संरक्षण का अधिकार देते हैं। बच्चों को समझाया गया कि किसी भी प्रकार की उपेक्षा, हिंसा या शोषण होने की स्थिति में वे निडर होकर संबंधित अधिकारियों या संस्थाओं से संपर्क कर सकते हैं।

इस अवसर पर हरियाणा बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य सुमन राणा ने बच्चों से संवाद करते हुए उन्हें आत्मविश्वास के साथ अपने अधिकारों को समझने और उनके लिए खड़े होने का संदेश दिया। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष उमेश कुमार चांदना और किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य बलराज सांगवान ने भी बच्चों को कानूनी संरक्षण से जुड़ी जानकारी दी। संस्थान के प्रधान बलदेव राज शिमला, मैनेजर गोपीनाथ शर्मा, महामंत्री करणवीर आर्य और श्रद्धांजलि ने भी कार्यक्रम में भाग लिया और बच्चों का उत्साहवर्धन किया।

कार्यक्रम के अंत में सभी बच्चों को भरोसा दिलाया गया कि समाज और प्रशासन उनके साथ है और उनके सुरक्षित व सम्मानजनक जीवन के लिए हर संभव मदद उपलब्ध है।

आपराधिक न्याय को मजबूत करने और दोषसिद्धि बढ़ाने के लिए हरियाणा की व्यापक रणनीति

संजना भारती/विज्ञप्ति द्वारा/चंडीगढ़। हरियाणा सरकार आपराधिक न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए अपने प्रयासों को तेज कर रही है, जिसमें चिह्नित अपराध मामलों में दोषसिद्धि दर बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। 26वीं राज्य-स्तरीय समिति की बैठक में बोलते हुए गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि वर्तमान दोषसिद्धि दर 61.17 प्रतिशत और निरंतर कार्रवाई के माध्यम से इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। डॉ. मिश्रा ने अधिकारियों से एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के निपटारे में तेजी लाने का आग्रह किया, जो न्यायिक दक्षता में सुधार, समय पर न्याय प्रदान करने और कानून प्रवर्तन एवं कानूनी प्रक्रिया में जनता के विश्वास को मजबूत करने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हरियाणा में नई गवाह संरक्षण नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया है जो एक अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और विश्वसनीय न्याय प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल: शेर प्रताप शेरी

संजना भारती संवाददाता

असन्ध। भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है और मंहगाई, भ्रष्टाचार, बदतर कानून व्यवस्था से जनता का जीना मुहाल है। प्रदेश में बढ़ रहे अपराध की घटनाएं और भ्रष्टाचार व जर्जर सड़कों से जनता में रोष है। उपरोक्त विचार हरियाणा किसान कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष शेर प्रताप शेरी ने करनाल रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं की मासिक बैठक को सम्बोधित करते हुए कहे। इस दौरान ब्राह्मण सभा के पूर्व प्रधान सुखदेव शर्मा, पूर्व सरपंच बिजेंद्र शर्मा, युद्धवीर सिंह, दिलबाग सिंह नंबरदार बल्ला व श्याम पाल रोहिल्ला ने भी कार्यकताओं को सम्बोधित किया। मंच का संचालन सिराजुद्दीन दूपेडी ने किया। शेरी ने कहा कि कांग्रेस कार्यकताओं को एकजुट होकर लोगों तक भाजपा के दावों की हकीकत बतानी होगी। कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें समाज के हर वर्ग के लोगों के हित सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि असंध नगरपालिका में स्टील कुर्सी घोटाले को लेकर एक माह से भी ज्यादा का समय हो गया लेकिन अभी तक कोई कारवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कुर्सी घोटाले की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कारवाई की जाए । शेरी ने कहा कि खाद न मिलने के कारण किसान परेशान है। सरकार ऐसी समस्याओं पर ध्यान न देकर सिर्फ अपनी उपलब्धियों का बखान करने में लगी है।

इस अवसर पर टीलू राणा, डॉ मांगे राम, प्रताप सिंह जय सिंह पुरा, सुकरमपाल सिंधड, पूर्व सरपंच जोगिंद्र सिंह, विजय बल्हारा, सुखबीर सिंधड, हरेन्द्र सिंह, मालक सिंह, कस्तूर सिंह, करनैल सिंह, जगदीश बेनीवाल सहित अन्य मौजूद रहे।

पांचाल समाज ने प्रारंभिक काल से भारत की सैन्य शक्ति और खाद्य सुरक्षा को किया सुदृढ़

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी

करनाल। भारत में पांचाल समाज की हर इकाई देश की सुरक्षा के लिए आयुध फैक्ट्री की तरह काम करती थी। प्रारंभिक काल से ही इस समाज ने लोहे से फौलादी हथियार बनाकर देश व समाज की सुरक्षा के लिए क्षत्रियों व नागरिकों को ताकत देने के साथ ही कृषि उपकरणों का निर्माण कर खाद्यान्न सुरक्षा में अहम भूमिका निभाई है। पांचाल समाज का इतिहास दर्शाता है कि तकनीकी कौशल, श्रम और सामाजिक उत्तरदायित्व किसी भी समाज को इतिहास में ऊंचा स्थान दिला सकते हैं। लोहे के औजारों से जंगल साफ करना, खेती को उन्नत बनाना और हथियारों से राज्य की रक्षा करना ये सब उनके जीवन का हिस्सा था। उनका दार्शनिक दृष्टिकोण श्रम की गरिमा और राष्ट्र सेवा में निहित था। संत स्वामी भीष्म जी महाराज जैसे महापुरुषों ने इस परंपरा को आध्यात्मिक और राष्ट्रवादी दिशा दी। यह समाज केवल एक जाति नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता की उस सृजनात्मक शक्ति का प्रतीक है, जिसने लोहे की धार से अन्न और स्वतंत्रता दोनों की रक्षा की।

भारतीय सभ्यता के इतिहास में ऐसे अनेक समाज हुए हैं जिन्होंने समय के प्रवाह में अपनी अमिट छाप छोड़ी। इनमें पांचाल समाज का नाम विशेष महत्व रखता है। यह समाज न केवल अपने कुशल धातुकर्म और उन्नत औजार निर्माण के लिए प्रसिद्ध रहा बल्कि अपने समय के राजनीतिक, सैन्य और सांस्कृतिक जीवन में भी इसकी भूमिका निर्णायक रही। पांचाल समाज को ऐतिहासिक स्त्रोतों में कभी महाजनपद के रूप में, कभी लोहार जाति के रूप में और कभी गणराज्य के रूप में उल्लेखित किया गया है। लोहे का आविष्कार और पांचाल समाज के उद्भव के पहलू पर विचार करें तो मानव इतिहास में लोहे का आविष्कार एक क्रांतिकारी घटना थी। लोहे के औजारों ने घने जंगलों को साफ कर खेती योग्य भूमि तैयार की। उन्नत हल, फाल, दरांती और अन्य कृषि औजारों ने कृषि उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि की। दूसरी ओर लोहे के हथियारों ने राजाओं और साम्राज्यों को सैन्य दृष्टि से सशक्त बनाया। पांचाल समाज का उद्भव इसी धातुकर्म-केंद्रित परिवर्तन से जुड़ा माना जा सकता है। प्रारंभिक काल में यह समाज कृषि औजारों और हथियारों का निमार्ता बना। इसने समाज की खाद्य सुरक्षा और राज्य की सैन्य शक्ति दोनों को सुदृढ़ किया।

इतिहासकार बताते हैं कि बौद्धकालीन साहित्य में पांचाल को सोलह महाजनपदों में गिना गया है। इसका विस्तार वर्तमान उत्तरप्रदेश के फरुर्खाबाद, बदायूं, बरेली और आसपास के क्षेत्रों में था। यह एक प्राचीन गणराज्य था, जहां शिल्प और कृषि दोनों का समान महत्व था। महाभारत में पांचाल का उल्लेख एक सशक्त और गौरवशाली राज्य के रूप में है। पांडवों का विवाह पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री द्रौपदी से हुआ था, जिससे पांचाल की राजनीतिक प्रतिष्ठा स्पष्ट होती है। मध्यकालीन सन्दर्भ में कश्मीर की महान शासिका रानी दीदा पांचाल/लोहार वंश से थीं, जिन्होंने जीवन में कोई युद्ध नहीं हारा। उनके शासनकाल में प्रसिद्ध इतिहासकार कल्हण ने राजतरंगिणी जैसी अमूल्य ऐतिहासिक कृति लिखी। पांचाल समाज केवल हथियार और औजार बनाने वाला समुदाय नहीं था बल्कि यह कर्मठता, आत्मनिर्भरता और राष्ट्र सेवा के सिद्धांतों से प्रेरित था। इनके श्रम में राष्ट्र निर्माण का दर्शन निहित था। लोहे की धार से केवल शत्रु का विनाश नहीं बल्कि अन्न उत्पादन की गारंटी भी सुनिश्चित होती थी। पांचाल समाज के लोग मानते थे कि श्रम ही सर्वोच्च पूजा है।

मध्यस्थता अभियान न्यायिक सुधारों की नई मिसाल: डॉ. इरम हसन

एसबी विशेष संवाददाता

करनाल। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव डॉ. इरम हसन ने कहा कि राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान न्यायिक सुधारों की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के निदेर्शानुसार एक जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक चल रहे इस 90 दिवसीय अभियान के तहत करनाल जिला भी सक्रिय भागीदारी निभा रहा है। उन्होंने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अदालतों में वर्षों से लंबित मामलों का समाधान सौहार्दपूर्ण, त्वरित व निःशुल्क तरीके से सुनिश्चित करना है। मिडिएशन (मध्यस्थता) एक ऐसा माध्यम है जिसमें दोनों पक्ष बिना किसी हार-जीत के सहमति से समाधान तक पहुंचते हैं। इससे जहां अदालतों पर बोझ कम हुआ है, वहीं आम जनता को भी राहत मिली है।

सीजेएम डॉ. हसन ने बताया कि अभियान के तहत जिले के सभी सरकारी विभागों के प्रमुखों और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को पत्र भेजकर आग्रह किया गया है कि वे ऐसे मामलों की पहचान करें, जिनमें आपसी सहमति से समझौता संभव हो। इन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर मध्यस्थता केंद्र भेजा जा रहा है। साथ ही आम जनता से भी अपील की गई है कि वे अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, संपत्ति या लेन-देन से जुड़े विवादों को मिडिएशन के जरिए सुलझाने की पहल करें। उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल विवादों के निपटारे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक रिश्तों की मरम्मत और आपसी विश्वास की पुनर्स्थापना का प्रयास है। इसका उद्देश्य है कि हर नागरिक न्याय तक आसानी और विश्वास के साथ पहुंच सके।

सीजेएम ने बताया कि मध्यस्थता एक स्वैच्छिक और गोपनीय प्रक्रिया है जिसमें तृतीय पक्ष (मध्यस्थ) दोनों पक्षों को मिलकर समाधान निकालने में मदद करता है। इसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाता, कार्यवाही निजी होती है, और परिणाम दोनों पक्षों की सहमति से तय होते हैं।